देश की विदेशी ऋण पर निर्भरता कम करने हेतु उठाए गए कदम

5979. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की विदेशी ऋण पर निर्भरता कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार को इस संबंध में क्या सफलता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) प्रत्येक ऋण करार की शर्तों के अनुसार विदेशी ऋणों का पुनर्भुगतान देय तिथियों पर किया जा रहा है । सरकार देश की विदेशी ऋण देयता के विषय में सचेत है और वह देश की ऋणग्रस्तता के स्तर एवं ऋण परिशोधन के संभाव्य बोझ पर लगातार नजर रखते हुए सरकार ने पहले से ही राजस्व प्राप्तियों में सुधार लाने, अनावश्यक और कम प्राथमिकता वाले व्यय को हटाने, निर्यात को बढ़ाने, कुशल आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने के लिए अदृश्य आयों को बढ़ाने, विदेशी निधियों के गैर-ऋणकारी निवेश को बढ़ाने और व्यय के वित्त-पोषण के लिए उधार ली हुई निधियों पर निर्भरता को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हुए हैं ।

इन उपायों के परिणामस्वरूप सरकार अतिरिक्त ऋणों की वृद्धि को काफी हद तक कम करने में समर्थ रही है । इस प्रकार 1993-94 के दौरान विदेशी ऋण में मात्र 740 मिलियन डालर की वृद्धि हुई थी । 1994-95 के पूर्वार्द्ध के दौरान ऋण में लगभग 270 मिलियन डालर की गिरावट आई है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वसूल किए गए ऋण और अग्रिम राशि

5980. **श्री आस मोहम्मद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए और वसूल किए गए ऋण के संबंध में कोई समीक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी किसी समीक्षा का ब्यौरा नहीं दिया है । तथापि, बैंकों में विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग अग्रिमों की सतत निगरानी की प्रणाली है । जैसे ही यह संकेत मिलता है कि किसी अग्रिम को वसूल करना कठिन हो सकता है, तभी इसकी विस्तृत रूप में समीक्षा की जाती है, जिसमें उस कार्य का संदर्भ जिसके लिए अग्रिम दिया गया था, कारोबार की प्रकृति, ऋणकर्ता का स्तर, प्रतिभूति की उपलब्धता आदि शामिल हैं । समीक्षा के आधार पर अग्रिम वसूल करने के लिए उपाय किए जाते हैं । सामान्यतः बैंक तभी वसूली के लिए मुकदमा दायर करते हैं जब वे वसूली लिए सभी प्रयत्न करके थक जाते हैं । ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) की स्थापना से बैंकों के वसूली निष्पादन में सुधार होने की आशा है ।

Loans to Unemployed SC/ST Youth is Gujarat

5981. SHRI RAJUBHAI A. PAR-MAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of unemployed youths belonging to Scheduled Castes[Scheduled Tribes|Backward and Tribals in Gujarat who have applied for bank loans to set up medium and small scale industries during the last three years; and